



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 21]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2012/पौष 29, 1933

No. 21]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2012/PAUSA 29, 1933

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2012

सं. 5/2012-सीमा-शुल्क ( गै.टै. )

सा.का.नि. 35(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1 लघु शीर्ष, क्षेत्र और आरंभन - (1) इन नियमों को 'प्रतिपाटन शुल्क प्रतिदाय (पाटन के वास्तविक अंतर से अतिरिक्त भुगतान) नियमावली, 2012 कहा जाएगा।

(2) क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है।

(3) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जबतक अन्यथा अपेक्षित नहीं हो-

(क) 'अधिनियम' का अर्थ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) है।

(ख) उन नियमों के सदर्थ में 'नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी' का अर्थ सीमा शुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण)

नियमावली, 1995 के नियम 3 के दृष्टिकोण से भारत के राजपत्र में अधिसूचना के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति है।

(ग) 'शुल्क' का अर्थ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) या उपधारा (1 क) के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क है।

(घ) 'कोष' का अर्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12ग के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष है।

(ङ.) 'आयातक' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसने माल की निकासी के लिए प्रविष्टि बिल दाखिल किया है और जिसने ऐसे माल पर शुल्क देयता का वहन करते समय पाटन के वास्तविक अंतर से अधिक प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान किया है।

(च) इन नियमों में प्रयुक्त गैर परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिए गए अर्थ हैं।

3. प्रतिपाटन शुल्क के अतिरिक्त भुगतान के प्रतिदाय का दावा करने की प्रक्रिया- (1) जहां आयातक ने किसी आयातित माल के संबंध में पाटन के वास्तविक अंतर से अधिक प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान कर दिया है वहां वह आयात के बंदरगाह पर सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त, जैसा मामला हो, के पास ऐसे अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय के लिए विहित प्रपत्र के अनुसार आवेदन दे सकता है।

(2) उपनियम 3(1) के आवेदन के साथ जिस प्रतिदाय का दावा किया गया है उसके संबंध में प्रतिपाटन शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाले दस्तावेज संलग्न होंगे।

4. प्रतिदाय दाखिल करने की समय सीमा-(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन सरकारी राजपत्र में अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन महीने के अंदर दाखिल किया जाएगा।

(2) जहां ऐसा शुल्क न्यायालय, अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकरण के निर्णय, डिक्री आदेश अथवा निदेश के परिणामस्वरूप वापस करने योग्य हो जाता है, वहां तीन महीने की सीमा का परिकलन ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश अथवा निदेश की तिथि से किया जाएगा।

5. प्रतिदाय के लिए आवेदन में कमी- (1) आवेदन प्राप्त होने पर सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त द्वारा इसकी पूर्णता के लिए इसकी जांच की जाएगी और यदि आवेदन में किसी ठोस तथ्यों की कमी पाई जाती है तो यह आयातक को कमियों का उल्लेख करते हुए एक महीने के अंदर लौटा दिया जाएगा।

(2) आयातक कमियो को दूर कर पुनः आवेदन इसकी प्राप्ति के एक महीने के अंदर सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त के पास कर सकता है।

(6) प्रतिदाय दावा का निपटान- यदि ऐसे प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति पर सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क का उपायुक्त इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिपाटन शुल्क पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वापस करने योग्य है तो वह तदनुसार ऐसा आदेश करेगा और इस प्रकार निर्धारित राशि आवेदन अथवा कमी दूर करने के बाद किए गए पुनः आवेदन नियम 5 के अंतर्गत प्राप्त होने के बाद 90 दिनों के अंदर आयातक को वापस कर दी जाएगी।

प्रावधान किया गया कि इस नियम के अंतर्गत वापस करने योग्य शुल्क की राशि आयातक को वापस करने की बजाए, यदि उसने ऐसे शुल्क को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दिया है, कोष में जमा कर दी जाएगी।

[फा. स. 354/126/2010-टीआरयू]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th January, 2012

**No. 5/2012-CUSTOMS (N.T.)**

**G.S.R. 35(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 AA of the Custom Tariff Act 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules, namely -

**1 Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Refund of Anti-Dumping Duty (Paid in Excess of Actual Margin of Dumping) Rules, 2012

(2) They extend to the whole of India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2 Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

- (b) "designated authority", in relation to these rules, means any person who is appointed as the designated authority by the Central Government by notification in the Official Gazette in accordance with rule 3 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995;
- (c) "duty" means the anti-dumping duty imposed under sub-section (1) or sub-section (1A) of section 9A of the Act,
- (d) "Fund" means the Consumer Welfare Fund established under section 12C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944),
- (e) "importer" means any person who has filed bill of entry for clearance of goods and while discharging duty liability on such goods has paid anti dumping duty in excess of the actual margin of dumping
- (f) Words and expressions used and not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Procedure for claiming refund of excess payment of Anti-dumping duty.-** (1) Where an importer has paid any anti-dumping duty in excess of the actual margin of dumping in relation to any imported goods, he may submit an application as per format specified for refund of such excess duty to the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, at the port of importation

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by documents evidencing payment of anti dumping duty in respect of which refund has been claimed.

**4. Time limit for filing refund.-** (1) Every application under these rules shall be filed within three months from the date of publication of notification, issued by the Central Government under sub-section (1) of section 9AA of the Act, in the Official Gazette

(2) Where such duty becomes refundable as a consequence of judgment, decree, order or direction of the Court, Appellate Tribunal or Authority, the limitation of three months shall be computed from the date of such judgment, decree, order or direction

**5. Deficiency in application for refund.-** (1) On receipt of the application, it shall be scrutinized for its completeness by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs and where the application is found to be deficient in any material particulars, it shall be returned to the importer within one month pointing out the deficiencies.

(2) The importer may re-submit the application after making good the deficiencies to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs within one month of receipt thereof

(6) **Disposal of refund claim.** — If, on receipt of any such refund application, the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, is satisfied that the whole or part of the anti dumping duty, as notified by the Central Government, is refundable, he may make an order accordingly and the amount so determined shall be refunded to the importer within 90 days of the receipt of the application or application resubmitted after rectification of deficiency, as the case may be, under rule 5

Provided that the amount of duty refundable under this rule shall, instead of being refunded to the importer be credited to the fund, if he had passed on the incidence of such duty to any other person

[F No 354/126/2010-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2012

सं. 6/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 36(अ).— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (6) तथा 9कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन तथा प्रतिपाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की वसूली एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, नामशः-

1. (1) ये नियम सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन तथा प्रतिपाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की वसूली एवं क्षति के निर्धारण के लिए) संशोधन नियमावली, 2012 कहे जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन तथा प्रतिपाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की वसूली एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 में,-

169 GI/12-2

(i) नियम 21 के बाद निम्नलिखित प्रविष्ट किए जाएंगे, नामशः-

"21 क पाटन के वास्तविक अंतर से अधिक अदा की गयी धनराशि का निर्धारण - (1) जहां आयातक को लगता है कि उसने किसी आयातित माल पर अधिनियम की धारा 9क के उपनियम (1) या उपनियम (1क) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क, ऐसे माल के संबंध में पाटन के वास्तविक अंतर से अधिक अदा कर दिया है, तो वह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे प्रलेखों के साथ जो कथित प्राधिकारी इस उद्देश्य के लिए निर्धारित करे, ऐसे माल के संदर्भ में पाटन के वास्तविक अंतर के निर्धारण के लिए एक आवेदन पत्र दायर कर सकता है।

2. जहां किसी सारभूत विवरण के संबंध में आयातक के आवेदन पत्र में कोई कमी पायी जाएगी, तो कमियों को दर्शाते हुए उसकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर आयातक को वापस कर दिया जाएगा तथा आयातक कमियों को दूर करके उसके बाद एक महीने के भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर सकता है।

3. संपूर्ण सूचनाओं के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे माल के संबंध में पाटन के वास्तविक अंतर के निर्धारण के लिए एक जांच शुरू करेगा।

4. पाटन के वास्तविक अंतर के निर्धारण में, जब निर्यात कीमत को इन नियमों के अनुरूप निर्मित किया जाता है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य में किसी परिवर्तन, आयात एवं पुनः बिक्री के बीच आयी लागत तथा बिक्री मूल्य में किसी दोलन को ध्यान में रखेगा जिसे परवर्ती बिक्री मूल्य में विधिवत दर्शाया जाता है।

(5) निर्मित निर्यात मूल्य की गणना करते समय प्रदत्त प्रतिपाटन शुल्क की धनराशि के लिए उसके निश्चयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी।

6. जहां नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी पाता है कि,

(क) आयात एवं पुनः बिक्री के बीच लागत में परिवर्तन है; और

(ख) बिक्री मूल्य में दोलन है जिसे परवर्ती बिक्री कीमतों में विधिवत दर्शाया गया है

तो उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए पाटन के वास्तविक अंतर का उपनियम (4) एवं (5) के तहत निर्धारण किया जा सकता है।

(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उपनियम (3) के तहत जाच के बाद माल के पाटन का वास्तविक अंतर निर्धारित करेगा और यदि माल पर प्रदत्त प्रतिपाटन शुल्क इस प्रकार निर्धारित पाटन के अंतर से अधिक होगा तो प्राधिकारी हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 9 महीने के भीतर किन्तु किसी भी मामले में 12 महीने से पहले आयातक को दोनों का अंतर वापस करने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगा।”

(ii) नियम 24 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्ट किए जाएंगे, नामशः:

“25 प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवर्चन”- (1) जहां कि किसी वस्तु को जिसपर कि प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाता हो, किसी ऐसे देश से, जिसमें इसके उद्भव का देश या निर्यात करने वाला देश, जिनको प्रतिपाटन शुल्क के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया गया है, भारत में बिना एसेम्बलड किये हुए, अधूरे या अपूर्ण रूप में निर्यात किया जाता है और उनको भारत में या ऐसे किसी भी देश में एसेम्बलड, पूर्ण निर्मित या पूर्ण किया जाता है तो ऐसे एसेम्बलिंग अंतिम रूप से विनिर्मित या पूर्ण करने के कार्य को यह माना जायेगा कि इसे प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवर्चन किया गया है यदि

(क) ऐसा कार्य प्रतिपाटन शुल्क की जाच के बाद या इसके सान्निह्यपूर्व शुरु किया गया हो या बढ़ाया गया हो और इसके कलपुर्ज और घटक उन उद्भव या निर्यात करने वाले देश से आयात किये गये हो जिन्हें प्रतिपाटन शुल्क की वसूली के लिए अधिसूचित किया गया हो; और

(ख) एसेम्बलिंग, पूर्ण निर्मित, पूर्ण करने के कार्य के परिणामस्वरूप होने वाला मूल्य एसेम्बलड, पूर्ण निर्मित, पूर्णतया तैयार वस्तु के मूल्य के पैंतीस प्रतिशत से कम हो।

स्पष्टीकरण: I “मूल्य” से अभिप्राय एसेम्बलड, पूर्ण या पूर्णतया विनिर्मित वस्तु की लागत घटा आयातित कल पुर्ज या घटकों के मूल्य से है

स्पष्टीकरण: II “इस मूल्य” की गणना के उद्देश्य के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार के (सबध में खर्च) रायल्टी पर किये गये खर्चों तकनीकी नो- हाउ शुल्क और परामर्श प्रभारों को शामिल नहीं किया जायेगा।

2 वस्तु के विवरण, नाम और सरचना में परिवर्तन करने की किसी प्रक्रिया के अधीन होने के पश्चात् जहां कि ऐसी कोई वस्तु, जिसपर प्रतिपाटन शुल्क लगता है, का उस उद्भव वाले या निर्यात करने वाले देश से भारत में आयात किया जाता है जिसको कि प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने के लिए अधिसूचित किया गया है तो ऐसे परिवर्तन के लिये यह माना जायेगा कि यह लागू प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवर्चन है यदि ऐसी वस्तु, जिसपर कि प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाता हो, के विवरण या नाम या सरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु का स्वरूप बदल जाता है चाहे यह अल्प रूप में हो या इससे टैरिफ वर्गीकरण, यदि कोई हो, ही क्यों न बदल जाता हो।

(3) जहा कि कोई वस्तु, जिस पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाता हो, को ऐसे निर्यातकर्त्ताओं या उत्पादकों या देश से भारत में आयात किया जाता है जिनपर प्रतिपाटन शुल्क नहीं लगाया जाता है तो ऐसे निर्यातों के लिये यह माना जाता है कि इससे प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवचन है यदि निर्यातकर्त्ता या उत्पादकर्त्ता, जिसे प्रतिपाटन शुल्क के लिये अधिसूचित किया गया है व्यापार के तरीकों, व्यापार के प्रतिपाटनों या इन वस्तुओं की बिक्री के चैनलों में फेर बदल कर देता है जिससे कि वह उन निर्यातकों या उत्पादकों या देशों के माध्यम से, जो कि प्रतिपाटन शुल्क से बाहर हैं, निर्यात करता है तो।

स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के उद्देश्य के लिये यह तब सुस्थापित होगा कि व्यापार के तरीकों, व्यापार प्रतिमानों, या विक्रय के चैनलों में फेर बदल कर दिया गया है यदि निम्नलिखित शर्तें संतुष्ट होती हैं-

(क) प्रतिपाटन शुल्क के लगाये जाने के अलावा किसी औचित्य, चाहे आर्थिक या अन्य किसी प्रकार का, का न होना

(ख) इस बात का प्रमाण की प्रतिपाटन शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों को इसी प्रकार के उत्पादों के मूल्य या गुणवत्ता की दृष्टि से कमजोर किया गया है

26. परिवचन को सिद्ध करने के लिये जांच कार्य की शुरुआत:-

(1) एतश्मिन् पश्चात् उल्लिखित बातों को छोड़कर प्राधिकृत प्राधिकारी, घरेलू उद्योग को या उसकी ओर से प्राप्त लिखित आवेदन पर यह सिद्ध करने के लिए जांच कार्य शुरू कर सकता है कि इस अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क के साथ कथित रूप से कोई परिवचन हुआ है या नहीं।

(2) ऐसे आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी बातों के बारे में पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए जिससे कि परिवचन विरोधी जांच शुरू करने को न्याय संगत ठहराया जा सके।

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) में निहित किसी बात के बावजूद नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी तरफ से भी जांच कार्य शुरू कर सकता है यदि वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत नियुक्त सीमा शुल्क आयुक्त या अन्य किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवचन करने की परिस्थितियां मौजूद हैं।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी लागू प्रतिपाटन शुल्क के प्रति किसी कथित छलावे के आस्तित्व और उसके प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि लागू प्रतिपाटन शुल्क के प्रति छलावे के क्रम में वस्तुओं का किया गया आयात पाटित पाया गया है: प्रावधान किया गया कि प्राधिकृत प्राधिकारी ऐसी जांच शुरू करने के पहले सरकार को निर्यातक देशों की सूची प्रस्तुत करेगा।



(5) नियम 6 के अंतर्गत दिये गये साक्ष्य और प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान इस नियम के अंतर्गत किये जाने वाले जांच कार्य में आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

(6) ऐसा कोई भी जांच कार्य 12 महीने में पूरा हो जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में जांच कार्य शुरू होने के 18 महीने से अधिक वक्त नहीं लगना चाहिए और ऐसा बिलम्ब होने का कारण भी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में बताया जाना चाहिए।

27. परिवचन का निर्धारण: (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, यह निर्धारित करने पर की प्रतिपाटन शुल्क का परिवचन किया जाता है, मौजूदा प्रतिपाटन शुल्क के परिवचन की मदों के आयात किए जाने अथवा प्रति पाटन शुल्क की लेवी के उद्देश्य से पहले ही अधिसूचित देशों को छोड़कर मूल रूप से अन्य देशों में निर्मित अथवा निर्यात किए जाने वाली मदों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की संस्तुति कर सकता है तथा ऐसी लेवी नियम 26 के अंतर्गत जाच आरंभ करने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू की जा सकती है।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को रिकार्ड करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा।

(3) केन्द्र सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुपालनार्थ नियम 26 के अंतर्गत जाच आरंभ करने की तारीख अथवा ऐसी तारीख जो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा संस्तुत की गई हो से ऐसे मदों के आयात सहित आयात की जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगा सकता है।

28 परिवचन की समीक्षा (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी ही पहल शुल्क लगाए जाते रहने की आवश्यकता अथवा किसी इच्छुक पक्षकार द्वारा जो समीक्षा की अपेक्षा के बारे में पर्याप्त ठोस जानकारी प्रस्तुत करता है उसके अनुरोध पर जहां कहीं अपेक्षित हो, समीक्षा कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत प्रारंभ की गई कोई भी समीक्षा, समीक्षा आरंभ किए जाने की तारीख से अधिक से अधिक 12 माह की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

[फा सं 354/126/2010-टीआरयू]

सजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

169 GI/12-3

नोट : मुख्य नियम दिनांक 1 जनवरी, 1995 की सा.का.नि. 1 (अ) द्वारा प्रकाशित, दिनांक 1 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सख्या 2/1995-सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा इनका पूर्ववर्ती संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 की सा.का.नि. सख्या 855 (अ) द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सख्या 86/2011 सीमा शुल्क द्वारा किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2012.

No. 6/2012-CUSTOMS (N.T.)

**G.S.R. 36(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9A and sub-section (2) of section 9AA of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely :-

1 (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995,-

(i) after rule 21, the following shall be inserted, namely:-

**“21A Determination of amount paid in excess of actual margin of dumping - (1)** Where an importer is of the opinion that he has paid any anti-dumping duty imposed under sub-sections (1) or sub-section (1A) of section 9A of the Act on any imported goods, in excess of the actual margin of dumping in relation to such goods, he may file an application for determination of the actual margin of dumping in relation to such goods before the designated authority in such form and accompanied by such documents as the said authority may specify in this behalf.

(2) Where the application referred to in sub-rule (1) is found to be deficient in any material particulars, the same shall be returned to the importer pointing out deficiencies within one month of the receipt thereof and the importer may, after making good the deficiencies, resubmit the application to the designated authority within one month thereafter

(3) On receipt of the application with complete information, the designated authority shall initiate an investigation to determine the actual margin of dumping in relation to such goods.

(4) In determining the actual margin of dumping, when the export price is constructed in accordance with these rules, the designated authority shall take into account any change in normal value, costs incurred between importation and resale and any movement in the sale price which is duly reflected in the subsequent selling price

(5) While calculating constructed export price, referred to in sub-rule (4), no deduction shall be made for the amount of anti-dumping duties paid when conclusive evidence of the same is provided

(6) Where the designated authority finds that there is change in,-

(a) costs incurred between importation and resale, and

(b) movement in the sale price which is duly reflected in the subsequent selling price,

the actual margin of dumping may be determined in accordance with the provisions of sub-rules (4) and (5) .

(7) The designated authority shall, after investigation under sub-rule (3), determine the actual margin of dumping for the goods and if the anti-dumping paid on the goods is in excess of the margin of dumping so determined, the authority shall make recommendation to the Central Government within nine months and in no case more than 12 months, from the date of receipt of the application, complete in all respects, to refund the difference between the two to the importer

169 GI/12-4

(ii) after rule 24, the following shall be inserted, namely:-

**“25. Circumvention of anti dumping duty. -** (1) Where an article subject to anti dumping duty is imported into India from any country including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of anti dumping duty, in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India or in such country, such assembly, finishing or completion shall be considered to circumvent the anti dumping duty in force if,-

(a) the operation started or increased after, or just prior to, the anti dumping investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of anti-dumping duty; and

(b) the value consequent to assembly, finishing or completion operation is less than thirty-five percent of the cost of assembled, finished or complete article

*Explanation I. -* ‘Value’ means the cost of assembled, complete or finished article less value of imported parts or components

*Explanation II. -* For the purposes of calculating the ‘value’, expenses on account of payments relating to intellectual property rights, royalty, technical know-how fees and consultancy charges, shall not be taken into account

(2) Where an article subject to anti dumping duty is imported into India from country of origin or country of export notified for the levy of anti-dumping duty after being subjected to any process involving alteration of the description, name or composition of an article, such alteration shall be considered to circumvent the anti dumping duty in force if the alteration of the description or name or composition of the article subject to anti dumping duty results in the article being altered in form or appearance even in minor forms regardless of the variation of tariff classification, if any.

(3) Where an article subject to anti dumping duty is imported into India through exporters or producers or country not subject to anti dumping duty, such exports shall be considered to circumvent the anti dumping duty in force if the exporters or producers notified for the levy of anti-dumping duty change their trade practice, pattern of trade or channels of sales of the article in order to have their products exported to India through exporters or producers or country not subject to anti dumping duty

*Explanation* - For the purposes of this sub-rule, it shall be established that there has been a change in trade practice, pattern of trade or channels of sales if the following conditions are satisfied, namely -

- (a) absence of a justification, economic or otherwise, other than imposition of anti-dumping duty,
- (b) evidence that the remedial effects of the anti-dumping duties are undermined in terms of the price and or the quality of like products.

**26. Initiation of investigation to determine circumvention** - (1) Except as provided herein below, the designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged circumvention of the anti dumping duty levied under section 9A of the Act, upon receipt of a written application by or on behalf of the domestic industry

(2) The application shall, *inter-alia*, contain sufficient evidence as regards the existence of the circumstances to justify initiation of an anti-circumvention investigation

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation *suo-motu* if it is satisfied from the information received from the Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances pointing to circumvention of anti dumping duty in force

(4) The designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged circumvention of the antidumping duty in force where it is satisfied that imports of the article circumventing an anti dumping duty in force are found to be dumped

Provided that, the designated authority shall notify the government of the exporting country before proceeding to initiate such an investigation.

(5) The provisions regarding evidence and procedures under rule 6 shall apply *mutatis mutandis* to any investigation carried out under this rule

(6) Any such investigation shall be concluded within 12 months and in no case more than 18 months of the date of initiation of investigation for reasons to be recorded in writing by the designated authority.

**27. Determination of circumvention -** (1) The designated authority, upon determination that circumvention of anti dumping duty exists, may recommend imposition of anti dumping duty to imports of articles found to be circumventing an existing anti dumping duty or to imports of article originating in or exported from countries other than those which are already notified for the purpose of levy of the antidumping duty and such levy may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under rule 26.

(2) The designated authority shall issue a public notice recording its findings

(3) The Central Government may, pursuant to the recommendations made by the designated authority, extend the anti dumping duty to imports of article including imports of such article from the date of initiation of the investigation under rule 26 or such date as may be recommended by the designated authority.

**28. Review of circumvention.-** (1) The designated authority may review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on its own initiative or provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the measures, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for the review

(2) Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of review

[F. No. 354/126/2010-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy

**Note -** The principal rule were notified vide Notification No.2/1995-Customs (N T), dated the 1<sup>st</sup> January, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1(E), dated the 1<sup>st</sup> January, 1995 and was last amended by Notification No.86/2011-Customs (N T), dated the 1<sup>st</sup> December, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 855(E), dated the 1<sup>st</sup> December, 2001